मेहनतकशों का पैग़ाम — मेहनतकशों के नाम

मज़दूर मोर्चा

साप्ताहिक

Email : mazdoormorcha1987@gmail.com
www.mazdoormorcha.com

Postal Reg. No. L/H.R/FBD/463-06 /R.N.I. No. 66400/97

- खुलासा : इंडिया टीवी और दैनिक जागरण वाले पैसा लेकर भाजपा के लिए दंगा फैलाने वाली खबरें करते हैं प्रसारित 3
- बैंकों के एन पी ए को लेकर एक नया चक्र समझ आया 4
- हिंदू संगठन ने निकाली रामनवमी पर हत्यारे शंभूलाल रैगर की झांकी 5
- राजकीय महिला महाविद्यालय से प्रिंसिपल ने लाखों की लकड़ी चोरी की 8

वर्ष 31 | अंक -14 | फ़रीदाबाद | 1-7 अप्रैल 2018 | फ़ोन : - 9999595632 | ₹ 2

राजनीति को व्यापार बनाने के साथ-साथ

अब शिक्षा व्यापार में भी उतरे मंत्री गूजर

अपने शिक्षण शोरूम का उद्घाटन करवाया मुख्यमंत्री खट्टर से

फ़रीदाबाद (म.मो.) दिनांक 25 मार्च रामनौमी के शुभ दिन, स्थानीय सांसद एवं केन्द्रीय मंत्री कृष्णपाल गूजर ने नहर पार सेक्टर 98 में शिक्षा व्यापार का एक बड़ा शोरूम खोला है। व्यापार अच्छा चले इसके लिये गूजर ने ब्रांड नेम भी डीपीएस का खरीदा है।

डीपीएस (दिल्ली पब्लिक स्कूल) आज के दिन, शिक्षा व्यापार में, एक जाना-मान मशहूर ब्रांड नेम है जिसके इस्तेमाल के बदले डीपीएस संस्था अच्छे खासे पैसे वसूलती है। हो सकता है संस्था ने मंत्री जी से पैसे न लेकर उसके बदले कोई काम निकलवा लिया हो। व्यापार अच्छा फले-फूले इसके लिये उद्घाटन भी पूरे ताम-झाम के साथ किसी बड़ी हस्ती से कराना जरूरी होता है, सो वह काम हरियाणा के मुख्यमंत्री खट्टर ने कर दिया।

करीब 8 एकड़ के प्लॉट में स्कूल के नाम पर बने इस शोरूम की लागत किसी भी तरह 2 करोड़ से कम नहीं और ज़मीन की कीमत 20 करोड़ से कम नहीं। सीबीएसई अथवा हरियाणा स्कूल शिक्षा बोर्ड से मान्यता प्राप्त करने के लिये ज़िला शिक्षा व अन्य अधिकारियों की रिश्वत 5-7 लाख अलग से। मंत्री होने के नाते

कृष्णपाल ने रिश्वत व सीएलयू के नाम पर लगने वाली रिश्वत तो खैर बचा ही ली होगी, लेकिन ज़मीन, इमारत, फ़र्नीचर व अन्य साज-सामान आदि पर कम से कम

25 करोड़ का खर्च तो बैठना तय है। अब कृष्णपाल जैसा राजनेता इतनी बड़ी रकम जनहित के लिये दान में तो देने से रहा। इस लागत पर यदि 2 प्रतिशत के हिसाब से 50 लाख वार्षिक भी न कमाये तो क्या फ़ायदा ?

मंत्री जी को यदि क्षेत्र की जनता का ही हित देखना होता तो यहां मोठूका में चल रहे नवोदय जैसा स्कूल खुलवाते। यह काम बहुत कठिन था तो एनआईटी में पचासों बरस से चल रहे केन्द्रीय विद्यालय जैसा स्कूल ही अपने मोदी भाई से कह कर खुलवा देते। यह भी बस का नहीं था तो खट्टर भाई से कह कर सेक्टर 98 के इर्द-गिर्द पटरी से उतरे खड़े सरकारी स्कूलों को पटरी पर ले आते जिनमें क्षेत्र के ग़रीब बालक कुछ पढ लेते। पर कृष्णपाल भला ऐसा क्यों करने लगे ? इससे उन्हें क्या लाभ होगा ? क्षेत्र की जनता यदि ज़्यादा पढ-लिख गयी तो फ़िर उनकी बहकाई में कैसे आयेगी ? नौकरी दिलाने के नाम पर युवाओं को बहका कर अपनी रैलियों में कैसे बुला पायेंगे।

मंत्री के मामा श्री के द्वारा फ़िलहाल उनके जो काले-पीले धंधे चलाये जा रहे हैं वे तो सदैव चलने वाले हैं नहीं। यह बात तो सीपी अमिताभ सिंह ढिल्लों ने ही साबित कर दी। यह तो तब है जब सत्ता में कृष्णपाल की पूरी भागीदारी है। कल को जब सत्ता से बेदखल हो जायेंगे तो कोई टके सेर भी नहीं पूछेगा। इसलिये भविष्य

शेष पेज दो पर

सुप्रीम कोर्ट, एनजीटी व पर्यावरण विभाग ने रिश्वतखोरों के भाव बढ़ाये

फ़रीदाबाद (म.मो.) पर्यावरण संरक्षण के नाम पर बना पर्यावरण विभाग व एनजीटी (नेशनल ग्रीन ट्रब्यूनल) जब से बने है भ्रष्ट अफ़सरों की मौज आ गयी है। एनओसी (अनापत्ति प्रमाणपत्र) देने के भाव कई गुणा बढ गये हैं। अरावली की पहाड़ियों को लेकर सुप्रीम कोर्ट के कड़े आदेश ने रिश्वत के भावों में और भी वृद्धि कर दी।

राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से सटी अरावली की मनोरम पहाड़ियों में बसने अथवा पंचतारा होटल बनाने को किस पूंजीपति का दिल नहीं चाहेगा ? रुकावट के बावजूद उक्त दोनों काम यहां कभी से होते आ रहे हैं। कानूनी रुकावट को हटाने अथवा अपनी आंखें मीचे रखने की एवज में सम्बन्धित अधिकारी चुट-मुट रिश्वत लेकर काम को होने दिया करते थे। परन्तु जब से पर्यावरण विभाग, एनजीओ व सुप्रीम कोर्ट के आदेशों द्वारा खनन व निर्माण कार्यों पर 'सख्त' रोक लगाई गयी है, तब से सम्बन्धित अधिकारियों द्वारा अपनी आंखें मीचे रखने व अवैध कामों को होने देने की रिश्वत के भाव कई गुणा बढा दिये गये हैं।

पर्यावरण प्रेमियों एवं आरटीआई कार्यकर्ता वरुण श्योकंद की अथक मेहनत व हंगामों के चलते सरकार को सर्वे कराना पड़ा। इसके मुताबिक 80 से अधिक अवैध फ़ार्म हाउस, अनेकों छोटी-मोटी कॉलोनियां इस क्षेत्र में खड़ी कर दी गयी हैं। और तो और 2 एकड़ के प्लॉट में डिलाइट ग्रुप पंचतारा होटल का निर्माण करने में जुटा है इसके लिये 40 फ़ीट गहरी खुदाई भी हो चुकी है। क्या सम्बन्धित विभागों के अधिकारियों को इतना बड़ा यह प्रोजेक्ट दिखाई नहीं दे रहा ? सुप्रीम कोर्ट व एनजीटी ने अपने आदेशों की पालना कराने के लिये क्या व्यवस्था की है ?

विदित है कि वन विभाग, पर्यावरण विभाग, खनन विभाग तथा नगर निगम का साझा दायित्व बनता है कि उक्त आदेशों का सख्ती से पालन कराये। उल्लंघना करने वालों के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही करने के अधिकार भी इन्हें प्राप्त हैं परन्तु स्वत: सिद्ध है कि इन सब ने अपने इन अधिकारों का प्रयोग करते हुए अपनी-अपनी औकात के अनुसार अच्छे-खासे नोट छाप लिये हैं। यदि पर्यावरण प्रेमी एवं वरुण श्योकंद जैसे सक्रिय आरटीआई कार्यकर्ता भी अपनी कीमत वसूल कर लेते तो न केवल पंचतारा डिलाइट होटल बन कर तैयार हो जाता बल्कि सैंकड़ो फ़ार्म हाउसों व अन्य होटलों के बनाने का सिलसिला भी शुरू हो जाता।

दरअसल सुप्रीम कोर्ट व एनजीटी ने अपने आदेशों में 'अनापत्ति' शब्द का प्रयोग करके रिश्वतखोरों व अवैध निर्माण करने वालों को गठजोड़ करने का एक खरीद-फरोख्त रास्ता दे रखा है। जब यह फ़ैसला हो ही चुका है कि इस क्षेत्र में कोई निर्माण या किसी प्रकार का खनन नहीं होगा तो फ़िर नहीं ही होना चाहिये। इसके लिये अनापत्ति प्रमाणपत्र का गुप्त रास्ता छोड़ा ही क्यों गया है ? इस संदर्भ में डिलाइट होटल के मालिक बंटी भाटिया का पूरी निडरता से दिया गया वह बयान अति महत्वपूर्ण है जिसमें वे कहते हैं कि वे कुछ भी अवैध नहीं कर रहे हैं, उनके पास सम्बन्धित विभागों के अनापत्ति प्रमाणपत्र हैं जिन्हें वे एनजीटी में 3 अप्रैल को पेश कर देंगे। इतना ही नहीं वे पूरी बेशर्मी के साथ उन्हें ब्लैकमेलर भी बता रहे हैं जिन्होंने अपने जोखिम पर यह मुद्दा एनजीटी के समक्ष उठाया है।

इस सम्बन्ध में निगमायुक्त मोहम्मद शाइन का जवाब बहुत ही ग़ैर जिम्मेवाराना लगता है जिसमें वे कहते हैं कि यदि होटल का निर्माण नियम विरुद्ध हो रहा होगा तो वे इसके विरुद्ध कड़ी कार्यवाही करेंगे। क्या मजाक है! अनखीर-सूरजकुंड सड़क के किनारे इतना बड़ा निर्माण कार्य चल रहा है और उन्हें पता ही नहीं कि यह नियमानुसार है या नियम विरुद्ध ? गली-कूचों के छोटे-मोटे अवैध निर्माण तो निगम के गिद्धों को झट से नज़र आ जाते हैं लेकिन सड़क किनारे का यह 2 एकड़ का निर्माण इन्हें पता ही नहीं।

मैं नरेंद्र मोदी आपका डेटा अमेरिकी कंपनियों को दे रहा हूं

नमो एप से डाटा चोरी होने की खबरों के बीच कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने मोदी पर कसा तंज, कहा आपका डाटा चोरी करके अमेरिकी कंपनियों को दे रहा हूं...

फेसबुक डाटा लीक कांड का पर्दाफाश और फेसबुक द्वारा डाटा कैंब्रिज एनालिटिका को बेचे जाने का खुलासा होने के बाद इसने राजनीतिक रंग लेना शुरू कर दिया है। जहां सोशल मीडिया पर यह मुद्दा छाया हुआ है, वहीं राजनेताओं ने भी डाटा चोरी मसले पर ट्वीटर वार शुरू कर दिया है।

कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि नमो एप की मदद से भाजपा लोगों का निजी डेटा लीक कर रही है। गौरतलब है कि पिछले कई दिनों से नमो एप को लेकर घमासान मचा हुआ है। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने भी फेसबुक डाटा चोरी को लेकर पीएम मोदी पर तंज कसा है।

शेष पेज दो पर